this project. The OECF (Japan) has also got an independent techno-economic appraisal of the project conducted recently and has fund the project to be acceptable for OECF (Japan) assistance. However, their decision to sanction loan assistance for this project is awaiting the final investment approval of the Government of India/Government of National Capital Territory of Delhi to this project, which has been sought for. The OECF (Japan) has asked for this approval to be conveyed to them by mid-August, 1996, in order to be able to include this project in their 1996-97 Loan Package.

The estimated period for the completion of the project will be 10 years from the date of commencement.

मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि

553. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आवास प्रबंधन एवं आश्रमगृह उन्नयन हेतु वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए उक्त वर्षों के दौरान कितनी राशि की मांग की गई थी;

(ग) इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत जिलावार कितने आवासों एवं आश्रमगृहों का निर्माण किया गया; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटश्वरलू) (क) और (ख) आवास प्रबंधन और आश्रमगृह के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई निधियां रिलीज नहीं की जा रहीं है। मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) के आवास और आश्रय उन्नयन की स्कीम के लिए 196.10 लाख रुपये की केन्द्रीय निधिय हडको को दी गयी है। इसी अवधि के लिए, राज्य ने 136.62 लाख रुपये की धनराशि अपने स्वयं के शेयर के रूप में मुहैया करायी है। निधियों के नियतन का निर्णय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर योजना आयोग द्वारा नियतित निधियों और शहरी गरीबी के प्रभाव क्षेत्र के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्र स्तर पर नेहरू रोजगार योजना के तहत जिलेवार, आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान आवास और आश्रय उन्नयन की स्कीम के लिए हडको को 14.25 लाख रुपये की धनराशि दी गयी थी। वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हडको को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया।

स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का अल्प उपयोग किया जाना

554. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता का केवल 54 प्रतिशत ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कुल स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) वर्ष 1995-96 के दौरान, 31.3.96 के अनुसार 83287 मे॰वा॰ की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में विद्युत उत्पादन 380.1 बि॰यू॰ था। वर्ष 1995-96 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 63 प्रतिशत था। देश में विद्युत कमी का मुख्य कारण उपलब्धता की तुलना में मांग का अधिक होना है।

(ख) अधिष्ठापित-क्षमता का संपूर्ण उपयोग न किए जाने के मुख्य कारणों में, यूनिटों का पुराना पड़ जाना, कम गुणवत्ता और मात्रा में कोयले की आपूर्ति, योजना-बद्ध और जबरन कामबंदी की उच्च दर और उपचारात्मक एवं वार्षिक तथा बड़े अनुरक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित न किया जाना शामिल है।

Setting up of Food Processing Units

555. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new Food Processing Units in the country, particularly in Punjab;